अब सौ से अधिक आबादी वाले मजरे, टोले सड़क से जुड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल शुरू की है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुगम संपर्कता परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से गांव, ग्राम पंचायत और 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला तथा मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के तहत चिन्हित बस्तियों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा. परियोजना अंतर्गत सड़कों का निर्माण मनरेगा यानी बीवी-जीरामजी योजना के माध्यम से कराया जाएगा. इसके लिए प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत को रुपए 3 करोड़ तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जनपद पंचायतों को राशि भी आवंटित कर दी गई है. परियोजना के तहत मजरे-टोले और सांदीपनि विद्यालयों तक बनने वाली सड़कों के लिए स्थान का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा. साथ ही सड़कों की डीपीआर तैयार करने के लिए सिपरी सॉफ्टवेयर और आरआईएमएस का उपयोग किया जाएगा.

ड्रोन से होगी निगरानी

परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी. निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

28 तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश

आयुक्त मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद अवि प्रसाद ने बताया कि परियोजना के तहत 28 मार्च तक डीपीआर तैयार कर उसकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए.

सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ

भोपाल/सागर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में शिक्षा का नया अध्याय लिखा जा रहा है और ज्ञानवीर विश्वविद्यालय युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देने का माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति ज्ञान और मूल्यों पर आधारित रही है और तक्षशिला तथा नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. उन्होंने महान शिक्षाविद् डॉ. हरि सिंह गौर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सागर में शिक्षा का नया सूर्योदय हुआ और यहां से पढ़े विद्यार्थी देश-विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं. सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जेसीनगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के युवाओं के सामर्थ्य और संकल्पों को नई दिशा देगा. मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञानवीर विश्वविद्यालय अपने माता-पिता के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है.

सड़क दुर्घटना में दंपति की मौत, पुत्री घायल

शहडोल. जिले के केशवाही थाना क्षेत्र के मझौली गांव में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस के अनुसार एक बड़े वाहन ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी. दुर्घटना में बाइक सवार लल्लू बैगा और उनकी पत्नी सरस्वती बैगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री सोहनी गंभीर रूप से घायल हो गई. राहगीरों की सूचना पर केशवाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायल बालिका को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

सिलेंडर की जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री गोविन्द सिंह ने सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो, इस हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में वितरक स्तर पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति निर्मित नहीं हो. राजपूत ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है एवं आपूर्ति बनी हुई है.

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के कारण आयात में हुई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किया जाये. ऑयल कम्पनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये वितरण प्रणाली में कुछ उपाय शुरू किये गये हैं. अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जा रही है. इसका उद्देश्य कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकना तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से समान वितरण सुनिश्चित करना है. इन परिस्थितियों में ऑयल कम्पनियों द्वारा तय किया गया है कि वर्तमान में चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा किसी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (होटल, मॉल, वल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि) को कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जायेगी.

> सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर खाद्य विभाग तथा ऑयल कम्पनी के अधिकारी और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर वाणिज्यिक और घरेलू सिलेण्डर की उपलब्धता की समीक्षा करें. जिले के बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की भी बैठक कर उनके पास उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं उनकी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति/स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी जाये.

एसीएस स्वास्थ्य की अध्यक्षता में समिति गठित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल,11 मार्च. राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित समग्र स्वास्थ्य योजना के अंतिम प्रारूप, नीति निर्धारण के साथ ही कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से परामर्श कर योजना को मंत्रि-परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य जबकि आयुक्त लोक स्वास्थ्य सदस्य-सचिव होंगे. समिति प्रस्तावित योजना के सभी आवश्यक तत्वों जैसे पात्रता, कवरेज, वित्तीय माडल, क्रियान्वयन संरचना तथा हितधारकों के परामर्श को समाहित कर विस्तृत योजना दस्तावेज तैयार करेगी, जिसे मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

परियोजनाएं समय में, गुणवत्ता के साथ पूरी हों

भोपाल, 11 मार्च. तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि समय पर परियोजनाएं पूरी होने से जनता को उनका लाभ मिल सकेगा. साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न हो. मंत्री सिलावट ने मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक में नर्मदा-तापी कछार इंदौर, जल संसाधन विभाग उज्जैन और नमामि क्षिप्रा परियोजना इकाई उज्जैन के अंतर्गत निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की समीक्षा की गई.

मंत्री ने आगामी सिंहस्थ-2028 से जुड़े कार्यों—कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना और क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण—की प्रगति की जानकारी लेकर इन्हें समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बुरहानपुर और धार जिलों में लगभग 5.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. मंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं की 15-15 दिन में समीक्षा कर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए.

संघ में नई संगठनात्मक संरचना की आहट, कल से होगी बैठक

मिलिंद मुजुमदार

इंदौर, 11 मार्च. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के समालखा में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होगी. संघ के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें संगठन की कार्यप्रणाली और ढांचे में संभावित बड़े बदलावों पर चर्चा की जाएगी.

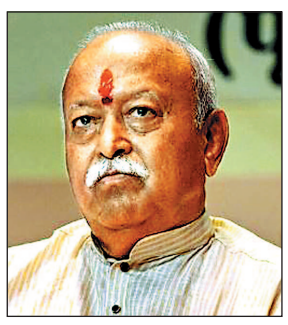

यह प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था मानी जाती है, जहां संगठन की भविष्य की दिशा तय होती है.

सूत्रों के अनुसार संघ अपनी पारंपरिक संगठनात्मक संरचना में बदलाव पर विचार कर रहा है. अभी तक संघ की व्यवस्था क्षेत्र, प्रांत और विभाग जैसी इकाइयों के आधार पर संचालित होती रही है. लंबे समय से यही ढांचा संघ के विस्तार और संचालन का आधार रहा है, लेकिन बदलते सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश को देखते हुए इसे अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में पहल की जा रही है.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संघ की संगठनात्मक संरचना को देश की प्रशासनिक प्रणाली के अनुरूप ढालने की योजना है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भविष्य में संघ की इकाइयां राज्य, संभाग और जिला स्तर पर कार्य करेंगी. इसके साथ ही राज्य प्रचारक, संभाग प्रचारक और जिला प्रचारक जैसे पदों की नई संरचना विकसित होने की संभावना है. इससे संगठन की कार्यप्रणाली को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है. संघ के जानकारों का मानना है कि यह बदलाव संगठन के तेजी से बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. पिछले एक दशक में संघ की शाखाओं और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों का देशभर में तेजी से विस्तार हुआ है. शिक्षा, सेवा और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी के कारण संगठनात्मक ढांचे को भी समय के अनुरूप ढालने की जरूरत महसूस की जा रही है.

> जानकारी के अनुसार यदि प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो नई व्यवस्था तुरंत लागू नहीं होगी. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और वर्ष 2027 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. समालखा में होने वाली इस बैठक में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और करीब 1450 प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और समकालीन चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है.

कमाल कर गया 'दिल से कहो अपने मोहन जी है ना' अभियान

- अब पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना
- रंग लाई मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम पर शुरू की गई पहल
- 25 मार्च को स्वास्थ्य शिविर का होगा समापन
- हजारों मरीजों को मिल रहा मुफ्त इलाज

प्रमोद व्यास

उज्जैन. महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों स्वास्थ्य सेवा का एक ऐसा अभियान चल रहा है, जिसने हजारों लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा दी है. हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान के लिए लगाए जा रहे नि:शुल्क जांच शिविर गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं. अब जल्द ही इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा.

इन शिविरों में मरीजों की जांच होने से बीमारी समय रहते पकड़ में आ रही है, जिससे इलाज आसान हो रहा है और लोगों के हजारों रुपये भी बच रहे हैं. उज्जैन शहर के सभी 54 वार्डों से लेकर जिले भर में यह शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और युवाओं से लेकर महिलाओं तक की नि:शुल्क जांच की जा रही हैं, आवश्यकता पड़ने पर सभी 11 निजी अस्पतालों में इन्हें भर्ती कर उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने किया था शुभारंभ-इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की थी, 25 जनवरी 2026 को विद्या भारती भवन, चिंतामण रोड पर 'दिल से कहो अपने मोहन जी हैं ना' अभियान के तहत इस नि:शुल्क हृदय रोग जांच अभियान की शुरुआत की गई थी. जिसका प्रभारी भाजपा अजा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण खोईवाल को नियुक्त किया हैं.

सीएम ने की तीन बार समीक्षा-मुख्यमंत्री स्वयं भी इस अभियान की कई बार समीक्षा कर चुके हैं ,भोपाल से लगाकर उज्जैन तक उक्त योजना के संबंध में जानकारी लेकर आंकड़े देखे गए हैं कि कितनी जांच हुई, कितने मरीजों को इलाज मिला, अभियान की सफलता को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है.

पूर्णिमा श्री सेवा संगठन को दिया जिम्मा-इस स्वास्थ्य शिविर के सेवा कार्य को जमीन पर सफल बनाने में पूर्णिमा श्री सेवा संगठन के संयोजक और भाजपा नेता सत्यनारायण खोईवाल की महत्वपूर्ण भूमिका है. सीएम के नाम चल रहे अभियान के तहत संगठन के प्रयासों से जिले भर में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका लाभ हजारों लोग ले रहे हैं.

11 निजी अस्पताल और पैरामेडिकल स्टाफ

करीब 11 बड़े निजी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच से हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है. उज्जैन में चल रहा यह अभियान अब सेवा, संवेदना और चिकित्सा सहयोग का ऐसा उदाहरण बन गया है, जहां मरीजों को समय पर जांच, मुफ्त इलाज और नई जिंदगी की उम्मीद एक साथ मिल रही है.

महंगे ऑपरेशन और सभी जांच निशुल्क

अभियान के तहत जिले में 101 से अधिक स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं. यहां इको, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, बीपी और शुगर की जांच के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी दी जा रही है. गंभीर मरीजों को आगे के उपचार के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जबकि एएसडी डिवाइस क्लोजर जैसे महंगे ऑपरेशन भी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से नि:शुल्क कराए जा रहे हैं. जरूरतमंद लोगों के आयुष्मान कार्ड भी शिविर में ही बनाए जा रहे हैं, जिससे इलाज में आर्थिक परेशानी न आए.

बच्ची के दिल में छेद, हुआ ऑपरेशन-इसी अभियान के दौरान इंद्रानगर की एक छोटी बालिका के दिल में छेद की गंभीर बीमारी सामने आई. चिकित्सकों की पहल से उसका ऑपरेशन भोपाल में किया. ऐसे कई मरीज, जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे थे, अब इस अभियान के माध्यम से उपचार पाकर स्वस्थ जीवन की ओर लौट रहे हैं.

इनका कहना है...मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अंतिम पंक्ति के गरीब परिवारों को भी योजना का लाभ मिल रहा है. जांच और इलाज सभी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में 25 मार्च को उक्त अभियान का समापन होगा.

सत्यनारायण खोईवाल ,प्रदेश उपाध्यक्ष, अजा मर्चा मप्र

पेज एक का शेष

दो राज्यों को 16,450 करोड़ की सौगात

पीएम मोदी ने एलपीजी संकट की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने देंगे. भारत संकट अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता: प्रधानमंत्री ने कहा, खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपकी चिंताएं स्वाभाविक हैं.

हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं. लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सत्ता में भाजपा-एनडीए सरकार है. जब भी हमारे नागरिक किसी दूसरे देश में फंसते हैं, हम उनकी मदद के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं. चाहे इराक में नर्सों को बचाना हो या यमन में आतंकवादियों से फादर टॉम को छुड़ाना हो, आज का भारत संकट के समय में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता.

अविश्वास प्रस्ताव खारिज

मैं विपक्ष नेता से पूछना चाहता हूं कि आप तब क्यों नहीं बोले. किसने रोका था. वो तो आपका अधिकार है कि आपकी पार्टी से कौन बोलेगा.

फ संशोधन-धारा 370 जैसी चर्चाओं से राहुल गायब रहे. एसआईआर पर चर्चा थी. विपक्ष के नेता को बोला गया कि आप बोलिए. नहीं बोले. उन्होंने सदन डिस्टर्ब किया.

16वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने 2014, 2015, 2017 और 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग नहीं लिया. उन्होंने 16वीं लोकसभा में केंद्रीय बजट पर किसी भी चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया.

उन्होंने किसी भी सरकारी विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 16वें, 17वें, 19वें, 20वें और 21वें सत्रों में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 19वें, 20वें, 22वें और 23वें सत्रों में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया और एक विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधायी चर्चा में भी भाग नहीं लिया. 18वीं लोकसभा में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया.

आईएएस के फार्म हाउस पर चल रहे जुआ अड्डे पर छापा....

पेज 1 का शेष....

मानपुर थाना प्रभारी लोकेंद्र हीहोर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अवलीपुरा स्थित कोठी निवास फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है. सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस टीम ने तड़के दबिश दी. मौके पर पहुंचने पर फार्म हाउस का मुख्य गेट बाहर से बंद मिला, जबकि अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थीं. इसके बाद पुलिस टीम पीछे के रास्ते से परिसर में दाखिल हुई, जहां बरामदे में रोशनी के बीच कई लोग ताश के पत्तों पर दांव लगाते यानी जुआ खेलते मिले. पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर 18 लोगों को पकड़ लिया.

हालांकि कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 लाख 67 हजार 971 रुपए नकद, 52 ताश के पत्ते, 10 नई ताश की गड्डियां, 30 मोबाइल फोन और दो कारें जब्त की हैं. जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत करीब 28 लाख 67 हजार 971 रुपए आंकी गई है. पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार दोपहर करीब तीन बजे एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया.

जगह बदल-बदलकर जुआ खिलाता है सरगना- पुलिस जांच में सामने आया है कि जुए का यह फड़ जगदीश राठौर उर्फ कूबड़ा नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो अलग-अलग स्थानों पर जुआ अड्डे संचालित करता है. जानकारी के मुताबिक, यह जुआ फड़ पहले 1 मार्च को लगना था, लेकिन किसी कारण से इसे टालकर 10 मार्च को आयोजित किया. पकड़े गए जुआरियों का कहना है कि वे पहली बार यहां खेलने पहुंचे थे. पुलिस फरार आरोपियों और मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है.

धार, उज्जैन और गुजरात तक के जुआरी पकड़ाए- गिरफ्तार किए 18 आरोपी मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों और गुजरात तक के रहने वाले हैं. पकड़े गए प्रमुख नामों में धार मनावर के अलिया उर्फ अलाउद्दीन, विजय मोदी, दीनदयाल जायसवाल, स्वपनिल डुंगरवाल, अखिलेश झंवर वहीं उज्जैन-बड़नगर के राहुल जैन, राहुल औरा, अभिषेक सरसोदे के अलावा इन्दौर-देवास के ओमप्रकाश राठौड़, बृजसिंह यादव, रवि चौधरी और गुजरात राजकोट नवीन पाटीदार व अन्य खरगोन, बड़वानी और झाबुआ के आरोपी भी शामिल हैं.

ये आरोपी हैं फरार, जिनकी तलाश जारी- पुलिस ने बताया कि जगदीश राठौड़ राजगढ़, गोपाल लिम्बोदी, पप्पू धोबी, आशीष जैन और केयरटेकर रंजीत जाट समेत 6 लोग फरार हैं. पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

पश्चिम मध्य रेल

शुद्धिपत्र संख्या 54/2025

निविदा सं 8125WCRTP-07 जिसके खुलने की तिथि 10/03/2026 थी, जो कि इस कार्यालय की निविदा नोटिस सं. EPS/122/2025 के तहत प्रकाशित की गई थी, इसमें निम्न संशोधन किए गए हैं– Tender No. & short Description **निविदा खोलने की तिथि : From:** 10/03/2026 , **To:** 23/03/2026, **List of Fittings :**NIL LIST OF FITTINGS. अद्धतन एवं पूर्ण जानकारी के लिए वेवसाईट https://www.ireps.gov.in देखें।

(हस्ता.)

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

तैयारियां अगले सप्ताह होंगे आईएएस के थोकबंद तबादले

4 संभाग कमिश्नर, 18 जिलों में नए कलेक्टर होंगे तैनात

कन्हैया लोधी

भोपाल, 11 मार्च. प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के थोकबंद तबादले की तैयारियां अब अंतिम चरणों में है. सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने गुणा-भाग कर संभावित तबादले और नए अफसरों की जमावट संबंधी सूची तैयार कर ली है और इसे मुख्य सचिव कार्यालय भेज दिया गया है.

मुख्य सचिव अनुराग जैन अब इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा कर सूची को अंतिम रूप देंगे. ऐसे में तय माना जा रहा है कि ये सूची अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगी, नई जमावट में कम से कम चार संभागों में नए कमिश्नर तैनात किये जा सकते हैं, वहीं डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदला जाएगा. इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष स्तर के अफसरों की भी नई जमावट हो सकती है. इस बहुप्रतीक्षित फेरबदल की चर्चा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही चल रही थी, लेकिन प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम चलने के कारण मैदानी अफसरों की जमावट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सका था, ये इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर के काम पूरा होने तक इस कार्य में लगे अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी थी, प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 7 फरवरी को पूरी हो चुकी है. विधानसभा का बजट सत्र भी पूर्ण हो गया है. अब होली और रंगपंचमी के बाद कभी भी आईएएस के तबादले सूची को सीएम की मंजूरी मिल सकती है.

मंत्रालय में होगी नई जमावट

संभावित फेरबदल में मंत्रालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं. वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डीपी आहुजा को बदला जा सकता है. अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों में संजय शुक्ला को दूसरी जिम्मेदारी जा सकती है.

भोपाल सहित एक दर्जन कलेक्टरों की हो सकती है वापसी

नई प्रशासनिक सर्जरी में कम से कम एक दर्जन कलेक्टरों की मैदानी पोस्टिंग से वापसी हो सकती है, उन्हें हटाकर नए अफसरों को भेजा जाएगा. ऐसे में वर्ष 2017 बैच के अफसरों को ज्यादा मौका मिल सकता है. इस बैच में एक दर्जन से अधिक अफसर हैं जो कि कलेक्टर बनने की प्रतीक्षा में है. वहीं कम से कम आधा दर्जन ऐसे अफसर भी होंगे.

मिले सकेतों के मुताबिक जो सूची प्रारंभिक तौर पर तैयार की गई है, उमसें भोपाल कमिश्र संजीव सिंह, शहडोल कमिश्र सुरभि गुप्ता, रीवा कमिश्र बाबू सिंह जामौद और नर्मदापुरम कमिश्र कृष्ण गोपाल तिवारी, जबलपुर कमिश्र धनंजय सिंह भदौरिया को भी बदला जा सकता है. इसके अलावा, ग्वालियर और चंबल संभाग के कमिश्रों को बदले जाने का मामला विचाराधीन है. इंदौर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60